SSD GD 2025

अवसर बैच

POLITY

Class - 06

→ संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(Right to constitutional remedies)

अनु० - 32

डा० भीम राव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है।

Art - 32

Dr. Bhim Rao ambedkar called it the heart and soul of the Indian constitution.

Art- 32 => Supreme Court जाने का अधिकार

Art - 226 => High Court " " " |

Supreme court
↑
High court
↑
district court

पाँच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। यथा -

① बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus) → व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाये।
② परमादेश (Madamus)
③ प्रतिषेध (Prohibition)
④ उत्प्रेषण (certiorari) तथा
⑤ अधिकार पृच्छा (Quo warranto)

→ मोहन, → पुलिस अधिकारी
↳ सोहन को गिरफ्तार
⇓
मोहन का कर्तव्य है कि वह सोहन को 24 घण्टे के अंदर 2 (within 2 hrs) मजिस्ट्रेट समक्ष लेकर जाए। लेकिन मोहन ऐसा नहीं करता है।

इसलिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण मोहन के खिलाफ जारी।

परमादेश (Mandamus) → हम आदेश देते हैं (we order)
↳ (किसके विरुद्ध जारी?) ⇒ सार्वजनिक अधिकारियों (Public officers)
⇒ सरकार (Government)
⇒ पंचायत (Panchayat's) नगरपालिका (Municipalty)
⇒ निगम (Corporations)
⇒ Superdinate courts (अधीनस्थ न्यायालय etc)

जब ये लोग अपना कर्तव्य निभाने से मना करें। (अपना कार्य करने से मना करें)

प्रतिषेध (Prohibition) → मना करना
↳ किसके विरुद्ध (against) जारी (issue)? ⇒ Subordinate court's (अधीनस्थ न्यायालय)

(क्षेत्राधिकार jurisdiction)

उत्प्रेषण (Certiorari) → मंगवा लेना
↳ विरुद्ध (against) ⇒ Subordinate courts) ↗ पहुँच गया district court

ex- मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मामला
Protection of fundamental Rights related matter
⇓
Supreme court / High court

अधिकार पृच्छा (Quo-warranto)
⇓
what's your authority? (आपका क्या अधिकार है?)
⇓
जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद (Public officer) के पद को अवैधानिक (illegal) तरीके से ग्रहण (Hold) करता है तो यह रिट उसके विरुद्ध जारी होती है।

आयरलैंड ⇐ राज्य के नीति निदेशक तत्व → (DPSP)
(Directive principles of state policy)
Taken from Ireland
↳ Part-IV, Art. 36-51
(भाग)

- भारतीय संविधान के भाग-4, अनुच्छेद-36 से 51 तक में 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' का वर्णन किया गया है।
- इसे 'आयरलैंड' के संविधान से लिया गया है।
- Part-4, Article 36 to 51 of the Indian constitution describe the 'Directive principles of state policy'.
- It has been taken from the constitution of Ireland.

Art-36 - राज्य की परिभाषा
Definition of state

- भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था।

- The aim of the Indian Constitution makers was to establish a welfare state in India.

DPSP का उद्देश्य → सरकारों के लिए निर्देश

objective of DPSP → कल्याणकारी राज्य (देश) की स्थापना establish a welfare state (country)

→ ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास

अनुच्छेद-37 में कहा गया है कि " इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू (En-forced) नहीं कराया जा सकता है। विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।

Art. 37- states that" The provisions of this part can't be enforced by any court; it shall be the duty of the state to use these elements in law-making.

F.R. → court से लागू (enforced)

Art. 37 → DPSP को court से लागू नहीं करवा सकते हैं।

अनुच्छेद - 38 - राज्य को यह निर्देश दिया गया हैं कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके

Art. 38 - Directs the state to promote public welfare and strive to establish a social order in which social, economic and political justice is assured to every individual.

Art. 38 → कल्याणकारी (welfare) → न्याय (justice)
① सामाजिक (social)
② आर्थिक (economic)
③ Political (राजनीतिक)

राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा, अनु. 39 (घ)

The state shall provide equal pay for equal work to every citizen, whether male or female, Article 39 (d)

Art-39(d) → Male (पुरुष) / Female (महिला) > समान कार्य के समान वेतन equal wor for equal payment

Art. 39 (A) ⇒ add on / जोड़ा गया ⇒ 42 (A) 1976
→ समान न्याय और निः शुल्क विधिक सहायता
equal justice and free legal aid

अनुच्छेद-40 के तहत् यह प्रावधान किया गया है राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठायेगा।

Art. 40 provides that the state shall take steps to constitute Gram panchayats.

Art. 40 → <u>पंचायतों का गठन</u>

⇒ संविधान संशोधन (Constitution Amendment)
↓
73(A) 1992

⇒ ग्राम पंचायतों की स्थापना ⇒ Part (भाग) → IX

⇒ Art. 243 - 243O, Schedule (अनुसूची) - 11

अनुच्छेद-41 - सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें।

Art. 41 - All citizens have the right to employment and education according to their abilities and to receive public assistance in class of unemployment old age, sickness and disability.

Art. 41 → योग्यता (Qualification) ⇒ रोजगार (employment)
⇒ शिक्षा (education)
⇒ बेरोजगारों को रोजगार

अनुच्छेद - 42 - राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों की अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

Art. 42 - The state shall endeavour to ensure that people are required to work in suitable and humane conditions and shall make provisions for maternity relief to woman.

→ Art. 42 → व्यक्ति → कोई कार्य करवाना है उसके अनुसार ↓ जिसे व्यक्ति करने में सक्षम।

अनुच्छेद - 43 - राज्य व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे।

Art. 43 - The state should encourage cottage industries on individual or co-operative basis.

Art - 43 ⇒ कुटीर उद्योग / cottage Industries] Rural Area

अनुच्छेद - 43 (ख) - राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन

अनु० 43 (ख) - सत्तानबेवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया है।

Art. 43B- Voluntary formation of state cooperative societies.

Art 43B - Added by the 97th constitutional Amendment Act 2011.

Art. 43 (B) => Add on → 97(A) 2011
↳ सहकारी समितियों का गठन (formed of cooperative societies)

ex => डेयरी उद्योग (Dairy Industries)

अनु० 44- सामान नागरिक संहिता

Art. 44- uniform civil code